



ResearchNext International Multidisciplinary Journal

Vol- 2, Issue- 3, July-September 2026

ISSN (O)- 3107-9725

Email id: editor@researchnextjournal.com

Website- www.researchnextjournal.com

ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमिका: सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रयास: सीकर जिला, राजस्थान के विशेष संदर्भ में

विनोद कुमारी

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान

डॉ० प्रिया मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर, अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान

Email: dr.priyamishra81@gmail.com, Orcid ID- <https://orcid.org/0009-0000-4602-2019>

Article Info: (Received- 12/04/2026, Accepted- 20/06/2026, Published- 05/07/2026)

DOI- [10.64127/rnimj.2026v2i3006](https://doi.org/10.64127/rnimj.2026v2i3006)

सारांश

ग्रामीण बालिका शिक्षा भारत की शैक्षिक समानता, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण समाज में परंपरागत मान्यताएँ, आर्थिक सीमाएँ, विद्यालय की दूरी, सुरक्षा संबंधी चिंता और बाल विवाह जैसी स्थितियाँ बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती रही हैं, वहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना विशेष महत्व रखती है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य सीकर जिला, राजस्थान के संदर्भ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह देखा गया कि आवासीय विद्यालय व्यवस्था ने वंचित वर्ग की बालिकाओं को सुरक्षित शैक्षिक वातावरण, पोषण, स्वास्थ्य, पुस्तक सामग्री, सहशैक्षणिक गतिविधियों और आत्मविश्वास निर्माण का अवसर दिया है। भारत सरकार के समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का लक्ष्य सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है (Ministry of Education, n.d.). राजस्थान में भी योजना के प्रवेश मानदंडों और निगरानी व्यवस्था में वंचित समुदायों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई है (Rajasthan Council of School Education, n.d.). अध्ययन से संकेत मिलता है कि सीकर जिले में केजीबीवी बालिकाओं के नामांकन, नियमित उपस्थिति, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और उच्च शिक्षा की आकांक्षा को बढ़ाने में प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालांकि अवसरचयना, पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन, करियर परामर्श और समुदायिक सहभागिता को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द— कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिका शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, बालिका सशक्तिकरण, सीकर जिला, राजस्थान

1. प्रस्तावना

भारत में शिक्षा को केवल साक्षरता प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि यह व्यक्ति और समाज दोनों के परिवर्तन का आधार है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक विकास से जुड़ी हुई है। जब एक बालिका शिक्षित होती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके निजी जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, बाल विवाह में कमी, आर्थिक सहभागिता, लोकतांत्रिक चेतना और परिवार की शैक्षिक आकांक्षाओं तक फैलता है। ग्रामीण भारत में बालिकाओं की शिक्षा के सामने अनेक बाधाएँ

रही हैं। इन बाधाओं में आर्थिक निर्धनता, घरेलू कामकाज का बोझ, विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, महिला शिक्षकों की कमी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सामाजिक रुढ़ियों प्रमुख हैं।

राजस्थान की सामाजिक संरचना में ग्रामीण जीवन, पारिवारिक परंपराएँ और लैंगिक भूमिकाएँ शिक्षा से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करती हैं। सीकर जिला शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के कई जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत आगे माना जाता है, फिर भी ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा की निरंतरता एक प्रमुख चुनौती बनी रहती है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित जिला साक्षरता विवरण के अनुसार सन् 2011 की जनगणना में सीकर जिले की कुल साक्षरता 71.91 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता 85.11 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि महिला साक्षरता इससे कम रही (Department of Education, Government of Rajasthan, n.d.). यह लैंगिक अंतर बताता है कि केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था जरूरी है जो ग्रामीण परिवारों का भरोसा जीत सके और बालिकाओं को सुरक्षित, निरंतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की उपयोगिता बढ़ती है। यह योजना उन बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से विद्यालय से बाहर हो जाती हैं या जिनकी नियमित शिक्षा बाधित होती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केवल कक्षा-कक्षा की शिक्षा नहीं देते, बल्कि आवासीय वातावरण में अनुशासन, जीवन-कौशल, सामूहिक जीवन, स्वास्थ्य-सचेतना, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि और नेतृत्व क्षमता का विकास भी करते हैं। इसीलिए यह योजना ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखी जा सकती है।

2. सीकर जिले का सामाजिक-शैक्षिक संदर्भ

सीकर जिला राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ शिक्षा के प्रति सामाजिक रुचि अपेक्षाकृत मजबूत रही है। फिर भी ग्रामीण समाज के भीतर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर वर्ग, आय, दूरी और पारिवारिक दृष्टिकोण के आधार पर असमानताएँ देखी जाती हैं। कई परिवार प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं को विद्यालय भेजते हैं, परंतु किशोरावस्था के बाद सुरक्षा, परिवहन, घरेलू श्रम और विवाह संबंधी दबावों के कारण उनकी शिक्षा बाधित होने लगती है। ऐसे परिदृश्य में आवासीय विद्यालय व्यवस्था ग्रामीण परिवारों को यह आश्वासन देती है कि बालिका सुरक्षित परिसर में रहेगी, नियमित भोजन प्राप्त करेगी और शिक्षिकाओं व वार्डन की निगरानी में अध्ययन करेगी।

सीकर जिले में केजीबीवी की प्रासंगिकता इस बात से भी समझी जा सकती है कि यहाँ अनेक बालिकाएँ ऐसे परिवारों से आती हैं जिनमें माता-पिता की शिक्षा सीमित होती है और उच्च कक्षाओं तक बालिका शिक्षा को लेकर स्पष्ट योजना नहीं होती। विद्यालय जब अभिभावक बैठक, ग्राम संपर्क और प्रवेश अभियान आयोजित करता है, तब परिवारों को यह समझने का अवसर मिलता है कि बालिका शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा और निर्णय क्षमता से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार विद्यालय परिवार और समुदाय के बीच संवाद का केंद्र बनता है।

3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की अवधारणा

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मूल उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में वंचित समूहों की बालिकाओं को आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा से जोड़ना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत इस योजना को कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई से जोड़ते हुए अधिक व्यापक बनाया गया है। मंत्रालय के अनुसार, यह योजना 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग की उन बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आती हैं (Ministry of Education, n.d.). योजना का लक्ष्य केवल प्रवेश दिलाना नहीं है, बल्कि प्राथमिक से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं का सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करना है।

राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन समग्र शिक्षा अभियान और राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान के दिशानिर्देशों में प्रवेश के लिए 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए तथा 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं के लिए प्राथमिकता के रूप में बताए गए हैं। दिव्यांग बालिकाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, वार्डन द्वारा नियमित सूचना भेजने, उपस्थिति की निगरानी करने और जिला तथा राज्य स्तर पर रिपोर्टिंग की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है (Rajasthan Council of School Education, n.d.). इससे स्पष्ट है कि यह योजना सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी लिंग आधारित शैक्षिक अंतर को कम करने पर बल दिया है। नीति में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु जेंडर इन्क्लूजन फंड की अवधारणा रखी गई

है (लवअमतदउमदज वपिदकपं, 2020). प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, समग्र शिक्षा 2.0 के अंतर्गत जेंडर समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, स्कूल सुरक्षा और मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी सुविधाओं जैसे प्रावधानों को महत्व दिया गया है (चतमे पदवितउजपवद ठनतमन, 2021). इस दृष्टि से केजीबीवी योजना राष्ट्रीय नीतिगत दिशा और स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का कार्य करती है।

4. साहित्य समीक्षा

बालिका शिक्षा पर उपलब्ध साहित्य बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की उपलब्धता के साथ-साथ विद्यालय का वातावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोगोई और गोस्वामी (2015) ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत संरचना की स्थिति का अध्ययन करते हुए पाया कि स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित छात्रावास, पर्याप्त भोजन, पुस्तकालय और स्वास्थ्य सुविधाएँ बालिकाओं की उपस्थिति और आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मंडल (2009) ने अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में आर्थिक निर्धनता, पारिवारिक श्रम और सांस्कृतिक अवरोधों को प्रमुख चुनौती के रूप में रेखांकित किया।

श्रीवास्तव (2015) ने गुजरात के संदर्भ में बताया कि केजीबीवी विद्यालयों द्वारा ग्राम-स्तरीय संपर्क, अभिभावक बैठक, स्थानीय निकायों की भागीदारी और महिला शिक्षकों की भूमिका बालिकाओं के नामांकन में सहायक होती है। आनंद और दास (2017) ने यह संकेत दिया कि आवासीय विद्यालयों ने उन बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जो पारिवारिक या सामाजिक कारणों से विद्यालय से दूर थीं। पांडे (2023) ने मध्य प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय महिला सहभागिता को योजना की व्यावहारिक सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार बताया।

राजस्थान के संदर्भ में वाधवा और आनंद (2021) ने कस्तूरबा विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की संतुष्टि का विश्लेषण करते हुए छात्रावास, भोजन, सुरक्षा, शिक्षक व्यवहार और सहशैक्षणिक गतिविधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। नायक (2023) ने केजीबीवी को बालिकाओं के सामाजिक विकास, आत्मविश्वास और सामुदायिक चेतना से जोड़ते हुए यह माना कि ऐसे विद्यालय ग्रामीण लड़कियों में स्वयं के अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि केजीबीवी की सफलता केवल प्रवेश संख्या से नहीं, बल्कि बालिकाओं के जीवन में आए सामाजिक और मानसिक परिवर्तन से मापी जानी चाहिए।

5. शोध के उद्देश्य

- सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की शैक्षिक भूमिका का विश्लेषण करना।
- बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट और उच्च कक्षाओं में प्रवेश पर योजना के प्रभाव को समझना।
- विद्यालयी अवसंरचना, छात्रावास, भोजन, सुरक्षा, पुस्तकालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
- अभिभावकों और समुदाय में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में आए परिवर्तन को पहचानना।
- योजना की प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

6. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के संकेतकों का उपयोग किया गया है। शोध का क्षेत्र राजस्थान राज्य का सीकर जिला रखा गया है। अध्ययन हेतु सीकर ग्रामीण क्षेत्र, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और खंडेला क्षेत्रों के चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को शामिल किया गया। जानकारी के स्रोतों में विद्यालय अभिलेख, उपस्थिति रजिस्टर, नामांकन विवरण, परीक्षा परिणाम, अवसंरचना से संबंधित निरीक्षण, शिक्षकों एवं छात्राओं से अनौपचारिक संवाद, अभिभावक प्रतिक्रिया और उपलब्ध सरकारी दिशानिर्देश शामिल किए गए। डेटा संग्रह के लिए साक्षात्कार, प्रेक्षण और दस्तावेज विश्लेषण को प्रमुख उपकरण के रूप में अपनाया गया। साक्षात्कार में छात्राओं, शिक्षकों, वार्डन, आश्रम माता, रसोइया, प्रधानाध्यापक और अभिभावकों से योजना की उपयोगिता, सुविधाओं और चुनौतियों पर जानकारी प्राप्त की गई। प्रेक्षण के माध्यम से विद्यालय परिसर, छात्रावास, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, पुस्तकालय, खेल सामग्री और सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया गया। दस्तावेज विश्लेषण में नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट और शैक्षिक प्रगति के अभिलेखों को देखा गया। अध्ययन का उद्देश्य किसी एक विद्यालय की प्रशासनिक समीक्षा करना नहीं, बल्कि सीकर जिले में योजना की समग्र शैक्षिक और सामाजिक भूमिका को समझना है।

7. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सीकर जिले के चयनित क्षेत्रों के आधार पर नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट, अवसंरचना और अभिभावक

संतुष्टि से संबंधित संकेतकों का विश्लेषण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: चयनित क्षेत्रों में नामांकन की स्थिति

अध्ययन क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन	औसत प्रति विद्यालय
सीकर ग्रामीण क्षेत्र	2	126	63
दांतारामगढ़ क्षेत्र	2	118	59
लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र	2	124	62
फतेहपुर क्षेत्र	2	112	56
खंडेला क्षेत्र	2	110	55
कुल	10	590	59

अध्ययन में चयनित 10 विद्यालयों में कुल 590 छात्राएँ नामांकित पाई गईं। प्रति विद्यालय औसत नामांकन 59 रहा। सीकर ग्रामीण क्षेत्र में औसत नामांकन 63 और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 62 पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि जहाँ अभिभावक जागरूकता और विद्यालयी पहुँच बेहतर है, वहाँ योजना के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता अधिक है। फतेहपुर और खंडेला क्षेत्र में नामांकन अपेक्षाकृत कम पाया गया, जो समुदायिक संवाद और प्रवेश अभियान को मजबूत करने की आवश्यकता बताता है।

उपस्थिति के संदर्भ में सीकर ग्रामीण क्षेत्र में 88 प्रतिशत, लक्ष्मणगढ़ में 86 प्रतिशत, दांतारामगढ़ में 84 प्रतिशत, फतेहपुर में 81 प्रतिशत और खंडेला में 79 प्रतिशत औसत उपस्थिति दर्ज की गई। यह अंतर दर्शाता है कि उपस्थिति केवल विद्यालय खुलने से नहीं बढ़ती, बल्कि सुरक्षित छात्रावास, नियमित भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षकों की उपलब्धता और बालिकाओं के भावनात्मक समर्थन से प्रभावित होती है। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय, खेलकूद और सहशैक्षणिक गतिविधियाँ बेहतर थीं, वहाँ छात्राओं की रुचि और नियमितता भी अधिक दिखाई दी।

सारणी 2: उपस्थिति और ड्रॉपआउट की स्थिति

अध्ययन क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन	औसत प्रति विद्यालय
सीकर ग्रामीण क्षेत्र	2	126	63
दांतारामगढ़ क्षेत्र	2	118	59
लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र	2	124	62
फतेहपुर क्षेत्र	2	112	56
खंडेला क्षेत्र	2	110	55
कुल	10	590	59

ड्रॉपआउट की स्थिति में खंडेला क्षेत्र में 11 प्रतिशत और फतेहपुर क्षेत्र में 9 प्रतिशत दर पाई गई, जबकि सीकर ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 6 प्रतिशत रही। ड्रॉपआउट के पीछे पारिवारिक आर्थिक दबाव, घर के काम में सहयोग, बाल विवाह की आशंका, अभिभावकों का अस्थायी पलायन, और उच्च कक्षाओं तक पढ़ाई जारी रखने के प्रति अनिश्चितता जैसे कारण सामने आए। केजीबीवी जैसे आवासीय विद्यालय इन कारणों को कम करने में सहायक हैं, परंतु इसके लिए अभिभावक परामर्श, घर-भेंट, पूर्व छात्रा संपर्क और स्थानीय पंचायत सहभागिता को नियमित बनाना आवश्यक है।

सारणी 3: अवसंरचना उपलब्धता (%)

अध्ययन क्षेत्र	स्वच्छ शौचालय	पेयजल	छात्रावास	रसोईघर	पुस्तकालय
सीकर ग्रामीण क्षेत्र	100	100	100	100	85
दांतारामगढ़ क्षेत्र	90	95	95	90	75
लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र	100	100	100	95	80
फतेहपुर क्षेत्र	85	90	90	85	70
खंडेला क्षेत्र	80	85	85	80	65

अवसंरचना के स्तर पर सीकर ग्रामीण और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। इन क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय, पेयजल, छात्रावास और रसोईघर की उपलब्धता उच्च स्तर पर पाई गई। खंडेला क्षेत्र में पुस्तकालय सुविधा 65 प्रतिशत और रसोईघर सुविधा 80 प्रतिशत के आसपास रही, जो सुधार की आवश्यकता बताती है। बालिका शिक्षा में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण परिवार अक्सर इन्हीं कारणों से बालिकाओं को विद्यालय भेजने में संकोच करते हैं। अतः भौतिक सुविधाएँ बालिका शिक्षा की निरंतरता के लिए मनोवैज्ञानिक आश्वासन का कार्य करती हैं।

सारणी 4: अभिभावक जागरूकता और संतुष्टि

अध्ययन क्षेत्र	जागरूक अभिभावक (%)	संतुष्ट अभिभावक (%)
सीकर ग्रामीण क्षेत्र	84	89
दांतारामगढ़ क्षेत्र	78	82
लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र	82	86
फतेहपुर क्षेत्र	74	78
खंडेला क्षेत्र	68	72

सामाजिक परिवर्तन के संकेतकों में बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, मंच पर बोलने की क्षमता, समूह गतिविधियों में भागीदारी, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता तथा उच्च शिक्षा की आकांक्षा को देखा गया। सीकर ग्रामीण और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रों में बालिकाओं में आत्मविश्वास और उच्च कक्षाओं में प्रवेश की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दी। कई छात्राओं ने यह बताया कि आवासीय वातावरण ने उन्हें नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और समूह में रहने की आदत सिखाई। अभिभावकों ने भी स्वीकार किया कि विद्यालय में रहने से बालिकाओं की सुरक्षा, भोजन और पढ़ाई की चिंता कम होती है। यह परिवर्तन शिक्षा के सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट करता है।

8. चर्चा

अध्ययन के निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों से मेल खाते हैं। गोगोई और गोस्वामी (2015) ने अवसररचना को उपस्थिति और प्रदर्शन का महत्वपूर्ण आधार माना था। वर्तमान अध्ययन में भी जिन विद्यालयों में स्वच्छता, छात्रावास, पुस्तकालय और भोजन व्यवस्था बेहतर रही, वहाँ उपस्थिति और संतुष्टि अधिक देखी गई। श्रीवास्तव (2015) के अनुसार ग्राम-स्तरीय संपर्क और स्थानीय निकाय की भूमिका नामांकन में सहायक होती है। सीकर जिले में भी जहाँ पंचायत और अभिभावक समिति सक्रिय पाई गई, वहाँ नामांकन और अभिभावक संतुष्टि बेहतर रही। नायक (2023) द्वारा वर्णित सामाजिक विकास की अवधारणा भी इस अध्ययन में पुष्ट होती है। केजीबीवी की छात्राएँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़तीं, बल्कि वे समूह जीवन, स्वच्छता, संवाद, नेतृत्व और आत्मरक्षा जैसे अनुभवों से गुजरती हैं। यह प्रक्रिया उन्हें परिवार और समाज में अधिक आत्मविश्वासी बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ऐसे समावेशी उपायों की आवश्यकता स्वीकार की गई है, जिनसे लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षा दोनों मिल सकें (Government of India] 2020). इस प्रकार केजीबीवी योजना को केवल विद्यालयी योजना के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज में लिंग-समानता की दिशा में नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में समझना चाहिए।

9. नीतिगत महत्व और भविष्य की दिशा

केजीबीवी योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह सरकारी विद्यालय व्यवस्था को आवासीय सहयोग से जोड़ती है। सामान्य ग्रामीण विद्यालयों में बालिकाएँ केवल दिन के समय अध्ययन करती हैं, जबकि केजीबीवी में शिक्षण, अनुशासन, स्वास्थ्य, भोजन, खेल, परामर्श और सांस्कृतिक प्रशिक्षण एक साथ उपलब्ध होते हैं। इससे बालिका की शैक्षिक उपलब्धि के साथ व्यक्तित्व विकास भी संभव होता है। यदि इस मॉडल को नियमित निगरानी, पर्याप्त बजट, प्रशिक्षित महिला स्टाफ, डिजिटल संसाधन और स्थानीय समुदाय के सहयोग से जोड़ा जाए, तो यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की निरंतरता को मजबूत कर सकता है।

नीतिगत दृष्टि से यह आवश्यक है कि केजीबीवी को केवल वंचित बालिकाओं के लिए आश्रयात्मक संस्था न माना जाए, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए विज्ञान, गणित, भाषा, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, पूर्व छात्राओं का डेटाबेस तैयार कर उन्हें प्रेरक वक्ता, मेंटर और समुदायिक शिक्षा दूत के रूप में जोड़ा जा सकता है। इससे वर्तमान छात्राओं को वास्तविक जीवन के उदाहरण मिलेंगे और अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा। इस अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। प्रस्तुत आँकड़े चयनित क्षेत्रों और विद्यालयी संकेतकों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें पूरे राजस्थान या सभी केजीबीवी विद्यालयों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। अध्ययन का उद्देश्य व्यापक प्रशासनिक मूल्यांकन के बजाय शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्तियों को समझना है। भविष्य में बड़े नमूने, दीर्घकालिक अध्ययन, छात्राओं के परीक्षा परिणाम, पूर्व छात्राओं की प्रगति और अभिभावक दृष्टिकोण के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अधिक गहन निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर भी वर्तमान अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सीकर जिले में केजीबीवी योजना ने ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

10. मुख्य निष्कर्ष

- सीकर जिले में चयनित केजीबीवी विद्यालय ग्रामीण बालिकाओं के नामांकन और नियमित उपस्थिति को

बढ़ाने में सहायक पाए गए।

- आवासीय व्यवस्था ने अभिभावकों की सुरक्षा संबंधी चिंता को कम किया और बालिकाओं की शैक्षिक निरंतरता को मजबूत किया।
- स्वच्छ शौचालय, पेयजल, छात्रावास, रसोईघर और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का सीधा संबंध छात्राओं की संतुष्टि और उपस्थिति से पाया गया।
- फतेहपुर और खंडेला क्षेत्र में ड्रॉपआउट और उपस्थिति से जुड़ी चुनौतियाँ अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दीं।
- छात्राओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व, स्वास्थ्य-जागरूकता और उच्च शिक्षा की आकांक्षा में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया।
- जहाँ पंचायत, अभिभावक समिति और विद्यालय प्रबंधन सक्रिय थे, वहाँ योजना का प्रभाव अधिक संतोषजनक पाया गया।

11. सुझाव

1. खंडेला और फतेहपुर जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रवेश अभियान और अभिभावक परामर्श कार्यक्रम चलाए जाएँ।
2. प्रत्येक केजीबीवी में पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री और विज्ञान-गणित प्रयोगात्मक संसाधनों को मजबूत किया जाए।
3. छात्राओं के लिए नियमित करियर मार्गदर्शन, जीवन-कौशल प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
4. वार्डन, आश्रम माता और शिक्षिकाओं को किशोरावस्था परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य और बाल संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए।
5. विद्यालय प्रबंधन समिति में माताओं, पूर्व छात्राओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाई जाए।
6. ड्रॉपआउट रोकने के लिए अनुपस्थित छात्राओं के घर-भेंट कार्यक्रम और सामुदायिक निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए।
7. उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी की सुविधा दी जाए।

12. निष्कर्ष

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरती है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यह योजना उन बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ती है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित हो सकती थीं। आवासीय व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और सहशैक्षणिक गतिविधियाँ बालिकाओं की निरंतरता और आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। सीकर जिले में योजना के प्रभाव से अभिभावकों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। बालिकाएँ अब अपने भविष्य, उच्च शिक्षा और सामाजिक भूमिका के प्रति अधिक जागरूक दिखाई देती हैं। हालांकि अवसंरचना, डिजिटल संसाधन, परामर्श सुविधा और समुदायिक सहभागिता में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। यदि इन क्षेत्रों पर व्यवस्थित रूप से काम किया जाए, तो केजीबीवी केवल विद्यालय नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रामीण समाज में शिक्षा-आधारित सामाजिक परिवर्तन के सशक्त केंद्र बन सकते हैं।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची—

1. Anand, S., & Das, B. (2017). बालिका शिक्षा में अंतर को पाटनारु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का अध्ययन. Journal of Indian Education, NCERT.
2. Department of Education, Government of Rajasthan. (n.d.), Districtwise literacy rate of Rajasthan as per Census 2011.
3. Gogoi, S., & Goswami, U. (2015). असम के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत संरचना की स्थिति. ResearchGate.
4. Government of India, (2020). National Education Policy 2020, Ministry of Education, <https://www.education.gov.in/>
5. Kumar, M. & Kushwaha, M. (2024). जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा और कस्तूरबा गांधी योजना का विश्लेषण.
6. Mandal, P. (2009). झारखंड में अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की शैक्षिक उन्नति में कस्तूरबा विद्यालय की भूमिका. Journal of Indian Education, NCERT.
7. Ministry of Education, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV, Samagra Shiksha- [https://samagra-education.gov-in/kgbv.html](https://samagra-education.gov.in/kgbv.html)
8. Nayak, L. N. 2023, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से बालिका के सामाजिक विकास की समझ. Journal of Studies in Dynamics and Change.
9. Pandey, G. (2023). मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन.
- 10- Press Information Bureau. (2021, December 1). Steps taken by the Government for Gender Inclusion Fund. Ministry of Education, Government of India. <https://www.pib.gov.in/>
- 11- Rajasthan Council of School Education. (n.d.). Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya: Admission, components and monitoring. Raj Shala Darpan. <https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/>
12. Shrivastava, G. (2015). गुजरात में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन हेतु अपनाई गई रणनीतियाँ. Journal of Indian Education, NCERT.
13. Wadhwa, M. A., & Anand, S. (2021). राजस्थान में कस्तूरबा विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की संतुष्टि का विश्लेषण. IJMER Journal.

Cite this Article

"विनोद कुमारी; डॉ. प्रिया मिश्रा", "ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमिकारु सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रयास: सीकर जिला, राजस्थान के विशेष संदर्भ में", ResearchNext International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3107-9725 (Online), Volume:2, Issue:3, July-September 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."